

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	315/2017	डॉ. भागीरथ कृष्णिया	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर। 4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, ज्योति नगर, जयपुर। 5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।
2.	914/2017	डॉ. इन्द्र प्रकाश	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर। 4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, ज्योति नगर, जयपुर। 5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल हॉस्पिटल, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।

आदेश की दिनांक : 16.12.2024

उपस्थित :-

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री दिनेश विश्नोई, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

- उपरोक्त दोनों अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा समान प्रकार के अनुतोष की मांग की गई है। अतः दोनों अपीलों का निस्तारण इस समान आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या-315/2017 डॉ. भागीरथ कृष्णिया बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
- अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी कनिष्ठ विशेषज्ञ, ईएनटी में 6 वर्ष से अधिक समय तक कार्यरत रहा था। इस कारण से आदेश दिनांक 01.07.2013 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 11.07.2011 से डीएसीपी स्कीम के अंतर्गत वेतनमान 15600-39100 ग्रेड-पे 7600 में पदोन्नत किया गया। इसके पश्चात आदेश दिनांक 24.01.2017 के द्वारा पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए अपीलार्थी को दिनांक 11.07.2013 के स्थान पर दिनांक 01.04.2014 से प्रमुख विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति दिये जाने का आदेश प्रदान किया गया। अपीलार्थी को पूर्व में जो पदोन्नति दिनांक 11.07.2013 से दी गई थी, वह डीएसीपी स्कीम के तहत दिनांक 11.07.2011 के दो वर्ष पश्चात दिनांक 11.07.2013 से दी गई थी, जो उचित थी। जिसको संशोधित कर दिनांक 01.04.2014 से किया जाना

उचित नहीं है। इस कारण से आदेश दिनांक 24.01.2017 जिसके द्वारा दिनांक में संशोधन किया गया है, वह गलत है। अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 24.01.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को डीएसीपी स्कीम के अंतर्गत दिनांक 11.07.2013 से वेतनमान 37,400-67,000 में ग्रेड पे 8,700/- में पदोन्नत किया गया था जो कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना एवं राय व वित्त विभाग की टिप्पणी के पैरा 15-16 के अनुसार संशोधन करते हुये उपरोक्त देय वेतनमान दिनांक 11.07.2013 के स्थान पर 01.04.2014 से देय होगा एवं इसी दिनांक से अपीलार्थी पदोन्नत माना जावेगा तथा उपरोक्त वेतनमान का लाभ दे दिया गया जो अपीलार्थी को देय नहीं था। इसलिये उपरोक्त विपरीत आदेश से संशोधित किया गया है, और अधिक दी गयी राशि की वसूली जीएफ एन्ड आर के नियम 124 के अनुसार की जानी नियमानुसार सही है। यह भी अंकित किया गया है कि आदेश दिनांक 24.01.2017 द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 13.06.2014 में जिन अधिकारियों को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 24 बी एवं 24 बीबी(5) के अन्तर्गत गठित स्क्रैनिंग कमेटी की अभिशंषा पर डी०ए०सी०पी० स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2013 से प्रमुख विशेषज्ञ के पद पर (वेतनमान 37400-67000 में ग्रेड-पे 8700/-) पदोन्नत किया गया था, को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 में किये गये संशोधन अनुसार नया नियम 24 बीबी डायनेमिक एस्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (डी.ए.सी.पी.) मंजूर करने के लिए प्रक्रिया (1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का शासन सचिव प्रत्येक वर्ष के प्रथम अप्रैल को ऐसे सदस्यों की सूची तैयार करेगा, जो उस वर्ष डायनेमिक एस्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (डी.ए.सी.पी.) के लिये पात्र हों तथा वित्त विभाग के परामर्श अनुसार चिकित्सकों को ग्रेड-पे 8700/- को दिनांक 11.07.2013 से स्वीकृत नहीं कर दिनांक 01.04.2014 से स्वीकृत की गयी है। फलस्वरूप आदेश दिनांक 24.01.2017 के द्वारा अपीलार्थी जो दिनांक 01.04.2014 से पूर्व दिनांक 28.02.2014 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो जाने के कारण डी०ए०सी०पी० स्कीम के अन्तर्गत पूर्व में दी गई दिनांक 11.07.2013 से पदोन्नति निरस्त की है। चूंकि डॉ० भागीरथ दिनांक 11.07.2011 को डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति पश्चात् दिनांक 01.04.2013 को 2 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण नहीं करते हैं, अतः दिनांक 01.04.2014 से डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत

पदोन्नति देय होने पर उक्त पदोन्नति निरस्त की गई है, जो उपलब्ध प्रावधान/नियमानुसार है।

4. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
5. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2013 (अनुलग्नक-1) के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को कनिष्ठ विशेषज्ञ, ईएनटी के पद पर 6 वर्ष और अधिक की नियमित राज्य सेवा पूर्ण करने के परिणामस्वरूप दिनांक 11.07.2011 से डीएसीपी स्कीम के अंतर्गत वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे-7600/- में पदोन्नति स्वीकृत की गई थी। प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी दिनांक 28.02.2014 को सेवानिवृत्त हो गया। सेवानिवृत्ति पश्चात् अपीलार्थी को संशोधित नियमों के अनुसार ग्रेड पे 8700 का लाभ दिनांक 11.07.2013 से दिया गया था। जहां तक आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2017 के द्वारा दिनांक 01.04.2014 से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाने के कारण डीएसीपी स्कीम के अंतर्गत पूर्व में दी गई दिनांक 11.07.2013 से पदोन्नति निरस्त किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 13.06.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम 24बी एवं 24बीबी(5) के अंतर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर डीएसीपी स्कीम के अंतर्गत दिनांक 11.07.2013 से प्रमुख मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर ग्रेड पे 8700 में पदोन्नत किया गया और उक्त पदोन्नति नियमों एवं प्रावधानानुसार की गई है। डीएसीपी स्कीम के अंतर्गत वित्त विभाग के परामर्श अनुसार दिनांक 11.07.2011 को डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पश्चात् 2 वर्ष की राज सेवा दिनांक 11.07.2013 को अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ दिया गया है और राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 जारी की गई, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख किया गया :-

"The Medical Officer including Dental who have completed total service of 18 years or more as on 11.07.2011 after regular appointment as per the provisions of the relevant recruitment rules and have been promoted under Finance Department Memorandum dated 09.08.2011 on the post of Senior Medical Officer including Dental/Deputy Chief Medical and Health Officer and equivalent post/Junior Specialist in grade pay of Rs. 6600/- as on 11.07.2011, shall be eligible for promotion on the post of Deputy Director/Chief Medical and Health Officer and equivalent post/Senior Specialist in grade pay of Rs. 7600/- after completion of service of two years instead of 6 years in the grade pay of Rs. 6600/-. The third DACP in grade pay of Rs. 8700/- shall be admissible on completion of service of four years instead of 6 years in the grade pay

of Rs. 7600/- subject to availability of vacant post as per prescribed ceiling of posts."

6. राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी मेमोरेण्डम दिनांक 10.07.2012 जिसमें निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :-

"The Senior Medical Officer including Dental/Deputy Chief Medical and Health Officer and equivalent posts/Junior Specialist who have completed total service of 18 years or more as on 11.07.2011 after regular appointment as per provisions of the relevant recruitment rules and have also completed at least 6 years service in GP of Rs. 6600/- or in the corresponding existing pay scale as on 11.07.2011 and have been promoted under Memorandum of even number dated 09.08.2011 on the post of Deputy Director/Chief Medical and Health Officer and equivalent posts/Senior Specialist in GP of Rs. 7600/- as on 11.07.2011 shall be eligible for promotion on the post of Principal Chief Medical Officer/Additional Director and equivalent posts/Principal Specialist in the GP of Rs. 8700/- after completion of service of 2 years instead of 6 years in GP of Rs. 7600/- subject to availability of vacant post as per prescribed ceiling of posts.

(ii) the existing word and figure "maximum 5%" appearing in remarks column against S.No. 4 shall be substituted by the word and figure "maximum 18%".

This order shall come into force w.e.f. 11.07.2011. The above Time Bound Promotions shall be admissible only after necessary amendments in the relevant service rules to this effect."

7. इस प्रकार उपरोक्तानुसार जारी अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 एवं मेमोरेण्डम दिनांक 10.07.2012 के अनुसार ही अपीलार्थी को डीएसीपी स्कीम के तहत 2 वर्ष पूर्ण होने पर ग्रेड पे 8700 का लाभ दिया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थीगण की अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य हैं।
8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपीलें स्वीकार की जाती हैं और आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2017 अपीलार्थीगण की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के संदर्भ में अपीलार्थीगण से वसूली नहीं की जावे।
9. मूल आदेश को अपील संख्या 315/2017 में एवं इसकी छायाप्रति अन्य अपील संख्या 914/2017 में संलग्न की जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)